RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 348
दि. 21.04.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

तमिलनाडु चुनाव में 'दाग' और 'धन' की दोहरी छाया, उम्मीदवारों की प्रोफाइल ने बढ़ाई चिंता

Chennai से लेकर पूरे Tamil Nadu में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को लेकर जो तस्वीर सामने आई है, उसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर गंभीर बहस छेड़ दी है। Association for Democratic Reforms की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के हलफनामों का विश्लेषण कई चौंकाने वाले संकेत देता है—जहाँ एक ओर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर करोड़पति प्रत्याशियों का दबदबा भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार कुल 3992 उम्मीदवारों के शपथपत्रों का अध्ययन किया गया, जिनमें से 722 यानी करीब 18 प्रतिशत उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले होने की जानकारी दी है। यह आंकड़ा अपने आप में इस बात का संकेत है कि चुनावी राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की भागीदारी अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि इन 722 उम्मीदवारों में से 404 यानी लगभग 10 प्रतिशत पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

यदि पिछली चुनावी तस्वीर से तुलना करें, तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में 13 प्रतिशत उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले थे और केवल 6 प्रतिशत पर गंभीर आरोप थे। इस बार इन दोनों श्रेणियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो यह दर्शाती है कि राजनीतिक दलों की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में सुधार की अपेक्षा अभी भी अधूरी है।

राजनीतिक दलों के स्तर पर देखें तो तस्वीर और भी जटिल हो जाती है। All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam के 170 में से 118 उम्मीदवारों, यानी लगभग 69 प्रतिशत ने अपने ऊपर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। Tamilaga Vettri Kazhagam के 231 में से 92 उम्मीदवार और Dravida Munnetra Kazhagam के 175 में से 70 उम्मीदवार भी इसी श्रेणी में आते हैं। अन्य दलों की स्थिति भी अलग नहीं है। Bharatiya Janata Party के 48 प्रतिशत, Indian National Congress के 50 प्रतिशत, Pattali Makkal Katchi के 50 प्रतिशत, Desiya Murpokku Dravida Kazhagam के 50 प्रतिशत, Communist Party of India के 60 प्रतिशत और Communist Party of India (Marxist) के 80 प्रतिशत उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। यह आंकड़े इस बात को रेखांकित करते हैं कि यह समस्या किसी एक दल तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है।

गंभीर आपराधिक मामलों के संदर्भ में भी स्थिति कम चिंताजनक नहीं है। एआईएडीएमके के 35 प्रतिशत, भाजपा के 27 प्रतिशत, पीएमके के 33 प्रतिशत और डीएमके के 18 प्रतिशत उम्मीदवारों पर गंभीर आरोप दर्ज हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या राजनीतिक दल जीत की संभावना को प्राथमिकता देते हुए उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को नजरअंदाज कर रहे हैं।

आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस चुनाव में धनबल का प्रभाव और अधिक स्पष्ट हो गया है। कुल उम्मीदवारों में से 981 यानी लगभग 25 प्रतिशत करोड़पति हैं। इनमें से 22 उम्मीदवार ऐसे हैं, जिनकी घोषित संपत्ति 100 करोड़ रुपये से अधिक है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि चुनाव लड़ना अब एक महंगा और संसाधन-प्रधान प्रक्रिया बन चुका है, जिसमें आम आदमी की भागीदारी सीमित होती जा रही है।

औसत संपत्ति के आंकड़े भी इस प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं। इस बार उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 5.17 करोड़ रुपये दर्ज की गई है, जो 2021 में 1.72 करोड़ रुपये थी। यानी कुछ ही वर्षों में यह आंकड़ा लगभग तीन गुना बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर चार उम्मीदवार ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति शून्य घोषित की है, जो इस असमानता को और अधिक उजागर करता है।

शिक्षा के स्तर पर तस्वीर अपेक्षाकृत संतुलित दिखती है। 43 प्रतिशत उम्मीदवार 5वीं से 12वीं तक शिक्षित हैं, जबकि 46 प्रतिशत स्नातक या उससे अधिक पढ़े-लिखे हैं। यह संकेत देता है कि शिक्षा के मामले में विविधता मौजूद है, लेकिन यह भी जरूरी है कि शिक्षा के साथ-साथ नैतिकता और सार्वजनिक जीवन की प्रतिबद्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो।

महिला भागीदारी के मामले में स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं कही जा सकती। कुल उम्मीदवारों में केवल 442 महिलाएं हैं, जो लगभग 11 प्रतिशत के बराबर है। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि राजनीति में लैंगिक संतुलन अभी भी एक दूर का लक्ष्य है और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए और प्रयासों की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर, यह रिपोर्ट केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने खड़े उन सवालों का आईना है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपराधिक पृष्ठभूमि, बढ़ता धनबल और सीमित महिला भागीदारी—ये सभी पहलू इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चुनावी सुधारों की जरूरत आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या राजनीतिक दल इन संकेतों को गंभीरता से लेते हैं और अपनी उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, स्वच्छता और संतुलन को प्राथमिकता देते हैं, या फिर यह प्रवृत्ति आगे भी इसी तरह जारी रहती है।

अति संवेदनशील बूथों पर सिर्फ सीआरपीएफ तैनाती, बंगाल में सख्त चुनावी सुरक्षा का खाका

Kolkata से निकलकर पूरे West Bengal में चुनावी माहौल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले प्रशासन और चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर उन मतदान केंद्रों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें 'अति संवेदनशील' श्रेणी में रखा गया है, और अब इन सभी बूथों की जिम्मेदारी देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल Central Reserve Police Force को सौंप दी गई है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब राज्य में चुनाव के दौरान हिंसा और गड़बड़ी की आशंका को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही थी। निर्वाचन आयोग और खुफिया एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट में साफ संकेत मिले हैं कि कुछ इलाकों में मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने, मतदाताओं को डराने या बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाओं की कोशिश हो सकती है। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए यह रणनीतिक कदम उठाया गया है, ताकि चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न हो सके।

इस बार 152 निर्वाचन क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान होना है, जो अपने आप में एक बड़ा प्रशासनिक और सुरक्षा चुनौती है। ऐसे में हर बूथ पर सुरक्षा बलों की तैनाती का निर्णय बेहद अहम हो जाता है। खासकर वे बूथ, जहां पहले हिंसा या गड़बड़ी की घटनाएं हो चुकी हैं या जहां तनाव की स्थिति बनी रहती है, वहां किसी भी प्रकार की ढिलाई प्रशासन के लिए भारी पड़ सकती है।

राज्य के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा 18 अप्रैल को जारी किए गए आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिन बूथों को अति संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है, वहां किसी भी हालत में स्थानीय पुलिस या अन्य बलों की तैनाती नहीं की जाएगी। यदि पहले से कहीं ऐसा आदेश जारी हुआ है, तो उसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और वहां केवल सीआरपीएफ की तैनाती सुनिश्चित की जाए।

यह निर्देश राज्य पुलिस, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को भेजा गया है, ताकि जमीनी स्तर पर किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने। इस आदेश का उद्देश्य साफ है—अति संवेदनशील बूथों पर पूरी तरह निष्पक्ष और बाहरी सुरक्षा बल की मौजूदगी सुनिश्चित करना, जिससे स्थानीय प्रभाव या दबाव की संभावना समाप्त हो सके।

चुनाव के दौरान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन इस बार उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। सीआरपीएफ को उन इलाकों में तैनात किया जा रहा है, जहां हालात सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण माने जा रहे हैं। यह बल न केवल सुरक्षा व्यवस्था संभालेगा, बल्कि मतदान केंद्रों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार रहेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम मतदाताओं के विश्वास को मजबूत करने में मदद करेगा। अक्सर संवेदनशील इलाकों में लोग डर के कारण मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते या उन पर दबाव बनाया जाता है। ऐसे में सीआरपीएफ की मौजूदगी उन्हें सुरक्षा का भरोसा दे सकती है, जिससे मतदान प्रतिशत भी बेहतर हो सकता है।

हालांकि, इस फैसले के साथ ही प्रशासन के सामने एक और चुनौती है—इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की प्रभावी तैनाती और समन्वय। इसके लिए राज्य पुलिस, केंद्रीय बलों और निर्वाचन आयोग के बीच बेहतर तालमेल जरूरी होगा। हर बूथ तक समय पर बलों की पहुंच, उनकी तैनाती और निगरानी एक जटिल प्रक्रिया है, जिसे सावधानीपूर्वक अंजाम देना होगा।

पिछले चुनावों के अनुभव भी इस बार की रणनीति को प्रभावित कर रहे हैं। कई बार यह देखा गया है कि संवेदनशील बूथों पर मामूली चूक भी बड़े विवाद का कारण बन जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार पहले से ही सख्ती बरती जा रही है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना को न्यूनतम किया जा सके।

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि चुनाव केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। ऐसे में इसकी पवित्रता और निष्पक्षता बनाए रखना हर संस्था की जिम्मेदारी है। सीआरपीएफ की तैनाती का यह निर्णय उसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

आधार सत्यापन का नया दौर: बिना डेटाबेस जुड़े तेज सुरक्षित और नागरिक-नियंत्रित पहचान प्रणाली

नई दिल्ली से आई यह खबर देश की डिजिटल पहचान व्यवस्था में एक बड़े बदलाव का संकेत देती है। Unique Identification Authority of India के तहत शुरू किए गए आधार आधारित ऑफलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम ने महज तीन महीनों में ही व्यापक स्वीकार्यता हासिल कर ली है। 100 से अधिक संस्थाओं का इससे जुड़ना इस बात का प्रमाण है कि यह व्यवस्था न केवल तकनीकी रूप से सक्षम है, बल्कि उपयोग में भी आसान और भरोसेमंद बन रही है।

यह नया सिस्टम पारंपरिक पहचान सत्यापन प्रक्रिया से अलग है, जहाँ हर बार केंद्रीय डेटाबेस से जुड़कर जानकारी की पुष्टि करनी पड़ती थी। अब ऑफलाइन वेरिफिकेशन के जरिए व्यक्ति अपनी पहचान साबित कर सकता है, वह भी बिना किसी लाइव डेटाबेस एक्सेस के। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे न केवल प्रक्रिया तेज होती है, बल्कि डेटा सुरक्षा के स्तर पर भी यह एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

इस व्यवस्था में क्यूआर कोड और डिजिटल साइन किए गए दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है। व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार अपनी जानकारी साझा करता है, जिसे संबंधित संस्था आसानी से सत्यापित कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अब बार-बार दस्तावेजों की फोटोकॉपी देने, पहचान पत्र दिखाने या लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाएगी।

सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि इस नई प्रणाली में नियंत्रण पूरी तरह व्यक्ति के हाथ में है। अब नागरिक खुद तय कर सकता है कि वह अपनी कौन-सी जानकारी साझा करना चाहता है और किसके साथ। यह व्यवस्था डेटा गोपनीयता के उस सिद्धांत को मजबूत करती है, जिसमें व्यक्ति की निजी जानकारी पर उसका अधिकार सर्वोपरि माना जाता है। सरकार का मानना है कि यह सिस्टम कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। बैंकिंग और फिनटेक कंपनियों के लिए ग्राहक सत्यापन की प्रक्रिया तेज और सरल हो जाएगी। होटल और इवेंट सेक्टर में पहचान जांच के लिए लगने वाला समय घटेगा, जिससे ग्राहक अनुभव बेहतर होगा। शिक्षा संस्थानों और विभिन्न वेरिफिकेशन एजेंसियों के लिए भी यह एक प्रभावी और समय बचाने वाला समाधान साबित हो सकता है।

डिजिटल इंडिया के व्यापक लक्ष्य के तहत यह कदम एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। देश में तेजी से बढ़ रही डिजिटल सेवाओं के बीच यह जरूरी हो गया था कि पहचान सत्यापन की प्रक्रिया भी उतनी ही तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो। ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन सिस्टम इसी दिशा में एक ठोस पहल है।

इसके साथ ही, यह सिस्टम उन क्षेत्रों में भी उपयोगी साबित हो सकता है, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी सीमित है या जहां रियल-टाइम डेटाबेस एक्सेस संभव नहीं है। ऐसे स्थानों पर भी अब पहचान सत्यापन आसानी से किया जा सकेगा, जिससे सेवाओं की पहुंच और व्यापक होगी।

हालांकि, इस नई व्यवस्था के साथ जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। लोगों को यह समझना होगा कि वे अपनी जानकारी किस तरह साझा करें और किन संस्थाओं पर भरोसा करें। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक सतर्क रहें और अपनी जानकारी केवल विश्वसनीय प्लेटफॉर्म्स पर ही साझा करें।

कुल मिलाकर, आधार आधारित ऑफलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम एक ऐसा कदम है, जो तकनीक और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। यह न केवल पहचान सत्यापन को आसान बनाता है, बल्कि व्यक्ति को उसकी जानकारी पर अधिक नियंत्रण भी देता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह प्रणाली कितनी तेजी से और किन-किन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करती है, लेकिन फिलहाल यह साफ है कि डिजिटल पहचान के क्षेत्र में भारत एक नए और अधिक सुरक्षित युग की ओर बढ़ रहा है।

19,694 करोड़ की कथित बैंक धोखाधड़ी में बड़ा एक्शन, आरकॉम के दो वरिष्ठ अधिकारी गिरफ्तार

मुंबई और नई दिल्ली से सामने आया यह घटनाक्रम देश की बैंकिंग व्यवस्था और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी Central Bureau of Investigation ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए Reliance Communications से जुड़े दो वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी एक ऐसे मामले में हुई है, जिसमें हजारों करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच चल रही है।

इस पूरे प्रकरण की शुरुआत State Bank of India द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से हुई। बैंक ने आरोप लगाया कि कंपनी को दी गई क्रेडिट सुविधाओं का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया और इसके बजाय संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के जरिए धन का दुरुपयोग किया गया। शिकायत के आधार पर सीबीआई ने नियमित मामला दर्ज किया, जिसमें कंपनी, उसके प्रमोटर Anil Ambani और अन्य अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया।

जांच के दौरान सामने आए तथ्यों ने इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया। यह मामला केवल एक बैंक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर देश के कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों तक फैला हुआ है। अकेले एसबीआई को करीब 2929.05 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जबकि कुल मिलाकर 17 बैंकों और वित्तीय संस्थानों को लगभग 19,694.33 करोड़ रुपये का भारी नुकसान झेलना पड़ा है। यह आंकड़ा इस मामले को हाल के वर्षों की सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी में शामिल करता है।

सीबीआई की जांच में यह सामने आया कि कथित रूप से कंपनी के भीतर ही कुछ अधिकारियों द्वारा नियंत्रित शेल कंपनियों का एक नेटवर्क बनाया गया था। इन फर्जी संस्थाओं के जरिए धन को एक जगह से दूसरी जगह घुमाया गया, जिससे वास्तविक लेनदेन को छिपाया जा सके। यह तरीका कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के मामलों में अक्सर अपनाया जाता है, जहां कागजों पर सब कुछ वैध दिखता है, लेकिन असल में धन का प्रवाह पूरी तरह संदिग्ध होता है।

इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी ने अपने ही समूह की अन्य संस्थाओं के साथ कथित तौर पर फर्जी सेवा-संबंधित लेनदेन दिखाए। इन लेनदेन के आधार पर लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) जारी किए गए और उन्हें डिस्काउंट कराया गया। बाद में ये सभी एलसी डिफॉल्ट हो गए, जिससे बैंकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह पूरी प्रक्रिया एक सुनियोजित वित्तीय हेराफेरी की ओर इशारा करती है, जिसमें कई स्तरों पर नियमों को दरकिनार किया गया।

सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में दो शीर्ष अधिकारियों—डी विश्वनाथ और अनिल काल्या—को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी का मानना है कि ये दोनों अधिकारी इस कथित धोखाधड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और इनके जरिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं।

यह मामला केवल एक कंपनी या कुछ अधिकारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की वित्तीय प्रणाली की उन कमजोरियों को भी उजागर करता है, जिनका फायदा उठाकर बड़े स्तर पर धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा सकता है। जब हजारों करोड़ रुपये का कर्ज दिया जाता है, तो उसकी निगरानी और उपयोग की जांच भी उतनी ही सख्ती से होनी चाहिए।

इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि क्या बैंकिंग प्रणाली में जोखिम प्रबंधन और निगरानी के तंत्र पर्याप्त रूप से मजबूत हैं। क्या बड़े कॉर्पोरेट लोन देने से पहले और उसके बाद पर्याप्त जांच-पड़ताल की जाती है? और यदि की जाती है, तो फिर ऐसे मामलों में इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है?

सीबीआई की आगे की जांच अब इस पूरे नेटवर्क को समझने पर केंद्रित है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कथित धोखाधड़ी में और कौन-कौन लोग शामिल थे, शेल कंपनियों का नेटवर्क कितना बड़ा था और इस पूरे प्रकरण में धन का वास्तविक प्रवाह किस तरह हुआ।

यह मामला आने वाले समय में और भी कई खुलासे कर सकता है, जो न केवल संबंधित कंपनी के लिए, बल्कि पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। फिलहाल, यह स्पष्ट है कि 19,694 करोड़ रुपये से अधिक के इस कथित घोटाले ने देश की बैंकिंग व्यवस्था को गहरा झटका दिया है और अब सभी की निगाहें जांच एजेंसियों की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

संपादकीय

मानव हित सर्वोपरि

मानव सभ्यता ने विज्ञान और तकनीक के सहारे असंभव को संभव करने की लंबी यात्रा तय की है, लेकिन हर नई खोज अपने साथ संभावनाओं के साथ-साथ संकट भी लेकर आती है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी दोराहे पर खड़ी एक शक्ति है, जो भविष्य को दिशा भी दे सकती है और भटका भी सकती है। दुनिया भर में इसके बढ़ते प्रभाव को लेकर उत्साह और आशंका दोनों समान रूप से मौजूद हैं। हाल ही में Pope Leo XIV द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं ने इस बहस को और गहरा कर दिया है। उनका मानना है कि यदि एआई को नैतिकता और मानवीय मूल्यों के साथ नियंत्रित नहीं किया गया, तो यह वैश्विक स्तर पर विभाजन, भय और हिंसा को जन्म दे सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मूल उद्देश्य मानव जीवन को सरल और अधिक प्रभावी बनाना है। यह स्वास्थ्य सेवाओं में सटीक निदान, शिक्षा में व्यक्तिगत मार्गदर्शन, और उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने जैसे अनेक क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। लेकिन यह तस्वीर का केवल एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि यह तकनीक धीरे-धीरे मानव निर्णयों और सामाजिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने लगी है, जिससे कई जटिल नैतिक प्रश्न खड़े हो रहे हैं। क्या मशीनें मानव विवेक का स्थान ले सकती हैं? क्या एल्गोरिदम के जरिए तय किए गए निर्णय निष्पक्ष होंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम इस तकनीक को नियंत्रित करने में सक्षम हैं? आज के समय में सूचना ही शक्ति है, और एआई इस शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन यही शक्ति जब गलत हाथों में पड़ती है, तो वह समाज के लिए खतरनाक बन जाती है। डीपफेक तकनीक इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इसके जरिए किसी भी व्यक्ति की नकली वीडियो या आवाज तैयार की जा सकती है, जो वास्तविक लगती है। इसका उपयोग चुनावों को प्रभावित करने, अफवाह फैलाने और व्यक्तियों की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है। इससे न केवल व्यक्तिगत स्तर पर नुकसान होता है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता भी खतरे में पड़ जाती है। साइबर अपराध के क्षेत्र में एआई ने अपराधियों को नई क्षमता प्रदान की है। पहले जहाँ धोखाधड़ी के लिए सीमित साधनों की आवश्यकता होती थी, अब एआई की मदद से बड़े पैमाने पर और अधिक सटीक तरीके से अपराध किए जा रहे हैं। आवाज की क्लोनिंग के माध्यम से ठग किसी व्यक्ति के परिचित बनकर पैसे मांगते हैं और लोग भावनाओं में बहकर ठगी का शिकार हो जाते हैं। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि तकनीकी विकास के साथ सुरक्षा उपायों को भी उतना ही मजबूत बनाना होगा। वित्तीय प्रणाली भी एआई के प्रभाव से अछूती नहीं है। उन्नत एल्गोरिदम बैंकिंग नेटवर्क की कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। यदि ऐसे हमले बड़े पैमाने पर होते हैं, तो यह केवल व्यक्तिगत नुकसान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी आर्थिक व्यवस्था को अस्थिर कर सकता है। इससे देशों के बीच आर्थिक तनाव और अविश्वास भी बढ़ सकता है। सामाजिक स्तर पर एआई के प्रभाव और भी जटिल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एल्गोरिदम इस तरह से काम करते हैं कि वे उपयोगकर्ता को वही सामग्री दिखाते हैं, जो उसकी पसंद के अनुरूप हो। इससे लोग एक तरह के "इको चैंबर" में फंस जाते हैं, जहाँ उन्हें केवल एक ही दृष्टिकोण दिखाई देता है। इससे समाज में विचारों का आदान-प्रदान कम होता है और ध्रुवीकरण बढ़ता है। यही वह स्थिति है, जिसके बारे में Pope Leo XIV ने चेतावनी दी है कि यह तकनीक लोगों को जोड़ने के बजाय उन्हें अलग-अलग खेमों में बांट सकती है।

पर्यावरणीय प्रभाव भी इस चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एआई को संचालित करने के लिए बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं, जो भारी मात्रा में बिजली का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, आवश्यक हार्डवेयर के लिए खनिजों की खुदाई पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। इस प्रकार, तकनीकी प्रगति की कीमत प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ सकती है।

हालांकि, इन सभी चुनौतियों के बावजूद यह मानना होगा कि एआई को पूरी तरह नकारना न तो संभव है और न ही उचित। यह तकनीक मानव जीवन को बेहतर बनाने की अपार क्षमता रखती है। चिकित्सा, कृषि, शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में इसका योगदान अमूल्य है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि हमें एआई चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि हमें इसे किस प्रकार और किस सीमा तक अपनाना चाहिए।

राष्ट्रीय लक्ष्यों हेतु नागरिक संबल भी मिले

> "राष्ट्र के उत्थान के लिये जो बड़े बदलाव के प्रयास होते हैं, यदि वे वाकई परिवर्तन के वाहक हों, तो जनता का सकारात्मक संबल मिलना चाहिए। हमें भविष्य की चुनौतियों के मुकाबले और राष्ट्रीय एकता के लिये कुछ त्याग भी करने चाहिए।

राजग सरकार का दावा है कि उसने देश में हमेशा बदलाव की राजनीति की है। भाजपा ने 1994 में राजनीति के हर चरण पर महिला आरक्षण का मुद्दा उठाया था। अब मौजूदा सरकार ने संसद का एक विशेष सत्र बुलाकर राजनीति में महिला आरक्षण लागू करने का प्रयास किया है। सरकार की मंशा थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिल जाए। इससे पहले जब राजग सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35-ए का 2019 में उन्मूलन किया था तो कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हुआ। कश्मीर से लद्दाख को अलग करके उसके पुनः परिसीमन का प्रयास किया। वैसे देश की कुरीतियों को हटाना भी अगर बदलाव कहें तो जब सरकार ने तीन तलाक को गैर-कानूनी घोषित कर दिया था तो इसे भी एक बदलाव कहा जा सकता है।

भाजपा के 47वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि देश में बदलाव का अभियान रुकेगा नहीं। हमारे बदलाव के एजेंडे में अभी भी एक बड़ी बात अधूरी है, एक बड़ा लक्ष्य अभी पूरा करना है, वह यह है कि अलग-अलग धर्मों, जातियों और वर्णों वाले देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाए। इस प्रायद्वीप जैसे बड़े देश में कभी केन्द्र और कभी राज्यों के चुनाव करते समय, शक्ति और पैसा बर्बाद करने की बजाय एक राष्ट्र और एक चुनाव की धारणा को साकार किया जाए। निस्संदेह, समान नागरिक संहिता लागू करने में धार्मिक कट्टरता या व्यावहारिक कठिनाइयां भी सामने आ रही हैं लेकिन इन्हीं पर आज विशेष चिंतन की जरूरत है। देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिये आज इसकी जरूरत है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंसा और कट्टरता हमारी राजनीतिक संस्कृति में नहीं होनी चाहिए। सरकार का मिशन हो सेवा और लक्ष्य हो विकास। असल में लक्ष्य यह है कि देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनना है तो इसमें एक राष्ट्र एक चुनाव और समान नागरिक संहिता लागू करके कुछ तरक्की की जा सकती है। थोड़ा इन लक्ष्यों पर चिंतन करें, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाने का प्रस्ताव है। आलोचक कहते हैं कि यह व्यावहारिक नहीं क्योंकि इस देश में हर पांच वर्ष बाद चुनाव नहीं होते। दल बदलकर सत्ता प्राप्त करने की इस राजनीति में सरकारें टूटती हैं, बनती-बिगड़ती हैं। तब मध्यावधि चुनाव भी करवाने पड़ जाते हैं। ऐसी वास्तविकता में एक राष्ट्र, एक चुनाव की संभावना कैसे फलीभूत होगी? इसका जवाब यह दिया जाता है कि जहां सरकार टूटे, वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और चुनाव एक ही समय पर करवाए जाएं क्योंकि इससे देश को भारी चुनावी खर्च से मुक्ति मिल जाएगी। यह भी सत्य है कि जब-जब जहां चुनाव घोषणाएं होती हैं, सत्तापक्षी-विपक्षी दल आरोपों की राजनीति करते हुए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। अगर एक देश एक चुनाव हो जाएगा तो यह पांच साल में केवल एक बार होगा। हमारा विचार यह है कि यह प्रस्ताव देश के हित में अवश्य है लेकिन राजनीतिक दलों को अपनी सत्ता मोह की राजनीति की जगह जनकल्याण पक्षीय राजनीति अपनानी पड़ेगी।

समान नागरिक संहिता जिसे यूसीसी भी कहते हैं, को लागू करने का विचार बहुत देर से भाजपा के एजेंडे में है। गौर करें कि इस देश में विभिन्न जातियां और विभिन्न धर्म हैं, इसलिए विवाह से लेकर बच्चा गोद लेने तक के अधिकतर कानून एक समान बना दिए जाएं। बेशक हमने अपने संविधान को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर रखा है, इसलिए आदर्श स्थिति तो यही है। हमारा देश जाति और धर्म में अस्मिताओं को लेकर बंटा हुआ है। हम कानून के तरीके से समान कानून के साथ एक जाति रहित समाज की कल्पना कर रहे हैं।

बेशक हम पाते हैं कि ब्रिटिश काल के कई पुराने कानून खत्म हुए हैं। सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए भी दस फीसदी आरक्षण मिल गया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है। देश बदला है, इसे और बदलना चाहिए। सपना राजनीतिज्ञ देखते हैं, लक्ष्य नेतृत्व जारी करता है और आम आदमी जागृति प्राप्त करके इसका पालन करते हुए अपने समाज को एक आदर्श समाज बना सकता है। लेकिन व्यवहार में हर आदमी का संकीर्ण हित उसके सामने सर्वोपरि हो जाता है। वह भूल जाता है कि हजारों लोगों ने डेढ़ सदी तक अंग्रेजों के साथ संघर्ष करके इस देश को आजादी दिलवाई है। अब इसे भौतिकवाद और निजी स्वार्थपरता के अंधेरों में गुम नहीं कर देना चाहिए। समान नागरिक संहिता और एक राष्ट्र एक चुनाव मौजूदा स्थिति से उठकर एक आदर्श समाज बनाने का सपना है। इस सपने को साकार करने में अभी तक बहुत कठिनाइयां आ रही हैं लेकिन भाजपा सरकार ने अपने दल की वर्षगांठ पर अपनी प्रतिबद्धता फिर इन सपनों को साकार करने के लिए जताई है। इसका अच्छे होने में तो कोई संदेह नहीं। हां, व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना ही पड़ेगा।

प्रेरणा

अकिंचन सेवा का आदर्श और समन्वय की ज्योति

भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि सच्चा धर्म किसी एक सीमित दायरे में बंधा हुआ नहीं होता, बल्कि वह समस्त मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसे ही विलक्षण संतस्वरूप व्यक्तित्व थे Hanuman Prasad Poddar, जिन्हें श्रद्धा और स्नेह से 'भाई जी' के नाम से जाना जाता है। उनका जीवन केवल भक्ति, साधना और सेवा का उदाहरण ही नहीं था, बल्कि वह धार्मिक समन्वय और निष्पक्षता का भी एक उज्ज्वल प्रतीक था।

भाई जी का सम्पूर्ण जीवन यह सिखाता है कि आध्यात्मिकता का वास्तविक स्वरूप संकीर्णता में नहीं, बल्कि व्यापकता में निहित है। वे Gita Press Gorakhpur के संस्थापक थे, जिसने सनातन धर्म के ग्रंथों को सरल, सुलभ और सस्ती कीमतों में जन-जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया। उनके द्वारा संपादित 'कल्याण' पत्रिका केवल एक धार्मिक पत्रिका नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसा मंच थी, जहाँ विभिन्न संप्रदायों, विचारधाराओं और आचार्यों के विचारों को समान सम्मान के साथ प्रस्तुत किया जाता था।

भाई जी के हृदय में किसी एक संप्रदाय के प्रति विशेष आग्रह नहीं था। वे वैष्णव, निम्बार्क, रामानन्द, रामानुज और अन्य अनेक परंपराओं के आचार्यों के प्रति समान श्रद्धा रखते थे। उनके लिए सभी मार्ग अंततः परम सत्य की ओर ले जाने वाले साधन थे। यही कारण था कि जब विभिन्न संप्रदायों के आचार्यों ने उन्हें दीक्षा देने का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने अत्यंत विनम्रता से इसे अस्वीकार कर दिया। उनका उत्तर अत्यंत गहन और दूरदर्शी था—यदि वे किसी एक संप्रदाय में दीक्षित हो जाते, तो 'कल्याण' पत्रिका की निष्पक्षता प्रभावित होती और वह सभी के लिए समान रूप से स्वीकार्य मंच नहीं रह पाती। यह निर्णय केवल एक व्यक्तिगत पसंद नहीं था, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण था। उन्होंने यह समझ लिया था कि समाज में पहले से ही अनेक मत-मतांतर मौजूद हैं और यदि एक ऐसा मंच तैयार किया जाए, जो सभी को जोड़ने का कार्य करे, तो यह समाज के लिए अधिक लाभकारी होगा। इस दृष्टिकोण में उनकी गहरी आध्यात्मिक समझ और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं।

एक बार एक पत्रकार ने उनसे सहज जिज्ञासा में पूछा कि वे किस संप्रदाय से संबंधित हैं। इस पर उनका उत्तर अत्यंत सरल, किन्तु गहन अर्थों से भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि वे 'भगवत संप्रदाय' के एक अकिंचन सेवक हैं। इस उत्तर में उनकी विनम्रता, समर्पण और व्यापक दृष्टिकोण तीनों झलकते हैं। 'अकिंचन' शब्द का अर्थ ही होता है—जिसके पास कुछ भी अपना नहीं है, जो पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित है। इस प्रकार उन्होंने स्वयं को किसी विशेष पहचान या बंधन से मुक्त रखते हुए केवल ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया।

उनका यह दृष्टिकोण आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है, जब समाज में विभाजन और संकीर्णता की प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। भाई जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म किसी एक विचारधारा को श्रेष्ठ सिद्ध करने में नहीं, बल्कि सभी विचारों का सम्मान करने में है। जब हम दूसरों के मार्ग को भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना अपने मार्ग को, तभी वास्तविक समरसता स्थापित होती है। भाई जी की विनम्रता भी उनके व्यक्तित्व का एक अद्भुत गुण थी। इतनी बड़ी संस्था के संचालक होने के बावजूद उन्होंने कभी स्वयं को महान या विशिष्ट नहीं माना। वे स्वयं को केवल एक सेवक के रूप में देखते थे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्ची महानता अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता में निहित होती है।

'कल्याण' पत्रिका के माध्यम से उन्होंने जो कार्य किया, वह केवल धार्मिक ज्ञान का प्रसार नहीं था, बल्कि वह समाज में नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का प्रयास था। उन्होंने विभिन्न संतों, आचार्यों और विद्वानों के विचारों को एक साथ प्रस्तुत करके यह दिखाया कि विविधता में भी एकता संभव है।

आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि स्वयं उन सिद्धांतों को जीकर दिखाया। उनका प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कार्य और प्रत्येक विचार समाज के व्यापक हित को ध्यान में रखकर किया गया था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करे, तो वह समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।

भाई जी का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को जोड़ना है, न कि विभाजित करना। जब हम अपने-अपने संप्रदायों की सीमाओं से ऊपर उठकर सोचते हैं, तभी हम उस सार्वभौमिक सत्य को समझ पाते हैं, जो सभी के भीतर समान रूप से विद्यमान है। अंततः, Hanuman Prasad Poddar का जीवन एक प्रेरणा है, जो हमें यह सिखाता है कि सच्चा सेवक वही है, जो स्वयं को शून्य कर दे और समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करे। उनका 'अकिंचन सेवक' होने का भाव हमें यह याद दिलाता है कि जब तक हमारे भीतर अहंकार और विभाजन की भावना बनी रहेगी, तब तक हम वास्तविक आध्यात्मिकता को प्राप्त नहीं कर सकते। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर यदि हम भी अपने भीतर समन्वय, विनम्रता और सेवा की भावना विकसित करें, तो यह समाज अधिक शांतिपूर्ण और समरस बन सकता है।

होर्मुज की उथल-पुथल के बीच अचानक मोदी से मिले कोरियाई राष्ट्रपति, चीन की उल्टी गिनती शुरू?

चीन ने भारत के खिलाफ अग्रेसिव रुख लेते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज के नाम बदल दिए थे। उसके बाद भारत ने एक डिप्लोमेसी अपनाई थी जिसके तहत भारत ने भी चीन के कुछ एरियाज के नाम बदले थे। अमेरिका के नजदीक जैसे-जैसे भारत जाने लगा तो चीन से दूरियां हमारी बढ़ना लाजमी है। अब भारत ने चीन के अगेंस्ट एक ऐसा कदम लिया है जो कि डिप्लोमेटिकली उसे वर्ल्ड ऑर्डर में चीन से बहुत आगे रख देगा। भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी से आगे जाते हुए दक्षिण कोरिया के साथ अपने रिलेशंस को अच्छे करने के लिए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति को भारत में इनवाइट किया। वो 19 से लेकर 21 तारीख तक तीन दिन की राष्ट्रीय विजिट पर भारत में आए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग के साथ बेहद अहम बैठक हुई। लगभग एक दशक तक, नई दिल्ली (भारत) और सियोल (दक्षिण कोरिया) के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी ज़मीनी हकीकत से ज़्यादा कागज़ों पर ही नज़र आई। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार जारी रहा, लेकिन 2018 में दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति मून जे-इन की यात्रा के दौरान जो राजनीतिक उत्साह दिखा था, वह धीरे-धीरे फीका पड़ गया। भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्ते कभी टूटे नहीं थे, लेकिन दोनों देशों की अपनी-अपनी तात्कालिक रणनीतिक मजबूरियों के कारण ये अक्सर पीछे छूट गए। दक्षिण कोरिया मुख्य रूप से उत्तर कोरिया के मुद्दों, अमेरिका के साथ अपने गठबंधन को संभालने और चीन पर अपनी भारी आर्थिक निर्भरता में उलझा रहा। इसके अलावा, वहाँ की बदलती घरेलू राजनीति और राष्ट्रपति के लिए केवल एक कार्यकाल वाले सिस्टम ने लंबी अवधि की रणनीतियों को बनाए रखना मुश्किल कर दिया। वहीं दूसरी ओर, भारत हिमालयी सीमा पर चीन के साथ तनाव को संभालने, पाकिस्तान से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं और अन्य बड़ी महाशक्तियों के साथ अपने कूटनीतिक एजेंडे में व्यस्त था। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच एक अहम द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बातचीत के दौरान मुख्य फोकस वैश्विक स्तर पर मची उथल-पुथल—खासकर ईरान और इज़राइल-अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष—पर ही रहा। दोनों नेताओं ने इस बात पर गहराई से विचार-विमर्श किया कि युद्ध और तनाव के इस मौजूदा दौर में भारत और दक्षिण कोरिया अपने आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को और अधिक मज़बूत कैसे बना सकते हैं। बैठक के बाद, पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति अपनी संवेदनशीलता का संदेश देते हुए दोनों नेताओं ने मिलकर एक पौधा भी लगाया। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से भी इस महत्वपूर्ण मुलाकात की झलकियां साझा की गई हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का ज़िक्र करते हुए कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हज़ारों सालों पुराना सांस्कृतिक जुड़ाव है। उन्होंने याद दिलाया कि 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूरीरत्ना और कोरियाई राजा किम-सुरो के बीच हुआ विवाह हमारी साझा और गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आधुनिक दौर में भी यह जुड़ाव कायम है—जहाँ एक तरफ भारत में 'के-पॉप' (K-Pop) और 'के-ड्रामा' (K-Drama) की दीवानगी तेज़ी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया के लोग भी भारतीय सिनेमा और संस्कृति को खूब पसंद कर रहे हैं।

दोनों देशों के आपसी रिश्तों में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) रहा है। 2009 में साइन किया गया और 2010 में लागू हुआ यह समझौता अब काफी पुराना माना जाता है। भारत अक्सर दक्षिण कोरिया के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर अपनी चिंता ज़ाहिर करता रहा है। दोनों देशों ने 2030 तक आपसी व्यापार को $50 अरब तक पहुँचाने का एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। क्या यह दौरा इस लक्ष्य को पाने के लिए ज़रूरी 'ऑक्सीजन' दे पाएगा? अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि इसके लिए राजनीतिक दबाव तो ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद बारीकी से काम को अंजाम देना भी उतना ही ज़रूरी है। यह दौरा राजनीतिक दबाव तो दे सकता है, लेकिन सिर्फ़ अपने दम पर नहीं। ऊँचे स्तर के दौरे इसलिए मायने रखते हैं, क्योंकि वे निवेशकों की अनिश्चितता को कम करते हैं। सरकारी अधिकारियों की गंभीरता का संकेत देते हैं और इंडस्ट्री को सिर्फ़ बातचीत से आगे बढ़कर काम को अंजाम देने के लिए बढ़ावा देते हैं। अगर दोनों नेता इस दौरे का इस्तेमाल सीईपीए से जुड़ी रुकावटों को दूर करने, समय-सीमा तय करने और कुछ खास क्षेत्रों की पहचान करने के लिए करते हैं, तो 2030 तक $50 अरब का लक्ष्य ज़्यादा भरोसेमंद हो जाता है। लेकिन असली परीक्षा यह मुख्य लक्ष्य नहीं है; असली परीक्षा यह है कि क्या दोनों पक्ष अपने व्यापारिक संबंधों को ज़्यादा संतुलित, व्यापक और कुछ चुनिंदा निर्मित वस्तुओं पर कम निर्भर बना पाते हैं। हालाँकि, 2018 की तुलना में 2026 के हालात पूरी तरह से अलग हैं। महामारी के बाद की दुनिया और अर्थव्यवस्थाओं द्वारा जोखिम कम करने की नीतियों ने दक्षिण कोरिया को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। एशिया अब केवल विकास की उम्मीदों पर नहीं चल रहा है। अब यह सप्लाई-चेन (आपूर्ति श्रृंखला) की असुरक्षा, समुद्री विवादों, तकनीकी होड़ और उत्पादन के लिए केवल चीन पर निर्भर न रहने के दबाव से तय हो रहा है।

अभियान

आस्था का स्पर्श, मन का उपचार: शिव धाम में विश्वास की अदृश्य शक्ति

भारतीय संस्कृति में रोग और उपचार की अवधारणा केवल शरीर तक सीमित नहीं रही, बल्कि मन, आत्मा और चेतना के संतुलन से जुड़ी रही है। प्राचीन काल से ही यह माना गया है कि जब मनुष्य का मन अस्थिर होता है, तब शरीर भी बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसी कारण हमारे ऋषि-मुनियों ने आध्यात्मिक साधना, ध्यान और ईश्वर की उपासना को जीवन का अभिन्न अंग बनाया। दक्षिण भारत के Tamil Nadu में स्थित Thiruneelakudi का Neelakandeswarar Temple इसी गहरे आध्यात्मिक विज्ञान का जीवंत उदाहरण है, जहाँ लोग केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के संतुलन को पुनः प्राप्त करने के लिए आते हैं।

यह मंदिर विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं के बीच प्रसिद्ध है, जो थायराइड और पीसीओएस जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ आने वाले लोग यह जानते हुए भी कि यह कोई चिकित्सा केंद्र नहीं है, एक गहरी आस्था के साथ यहाँ आते हैं। उनके लिए यह स्थान किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन की शुरुआत होता है। यह वही परिवर्तन है, जो व्यक्ति को अपनी बीमारी से लड़ने की मानसिक शक्ति प्रदान करता है।

इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा Neelkanth के रूप में की जाती है। समुद्र मंथन की कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश है। जब संसार संकट में पड़ा, तब शिव ने विष को अपने भीतर धारण किया, उसे बाहर नहीं निकाला और स्वयं पीड़ा सहकर दूसरों की रक्षा की। यह त्याग और सहनशीलता का सर्वोच्च उदाहरण है। इसी कथा से यह भाव भी उत्पन्न होता है कि जो स्वयं पीड़ा को धारण कर सकता है, वही दूसरों के दुख को समझ सकता है और उसे दूर करने की शक्ति रखता है।

मंदिर की परंपराओं में यह कथा जीवित है। यहाँ तेल अर्पित करने की विशेष परंपरा है, जो उस घटना की स्मृति है जब माता पार्वती ने शिव के कंठ की जलन को शांत करने के लिए तेल अर्पित किया था। श्रद्धालु जब इस अनुष्ठान में भाग लेते हैं, तो वे केवल एक क्रिया नहीं करते, बल्कि अपने भीतर के तनाव, भय और पीड़ा को भी प्रतीकात्मक रूप से समर्पित कर देते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें मानसिक रूप से हल्का और संतुलित बनाती है।

यहाँ मिलने वाली विभूति को विशेष महत्व दिया जाता है। इसे केवल एक धार्मिक प्रसाद नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का माध्यम माना जाता है। लोग इसे अपने गले पर लगाते हैं और विश्वास करते हैं कि इससे उनकी समस्याओं में राहत मिलेगी। यह विश्वास ही इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जब व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ किसी क्रिया को करता है, तो उसका मन उस दिशा में सकारात्मक रूप से कार्य करने लगता है। यही सकारात्मकता उसके शरीर पर भी प्रभाव डालती है।

पीसीओएस जैसी समस्या आज के समय में महिलाओं के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। यह केवल शारीरिक असंतुलन नहीं, बल्कि मानसिक तनाव, आत्मविश्वास की कमी और सामाजिक दबाव का भी कारण बनती है। ऐसी स्थिति में जब महिलाएँ इस मंदिर में आती हैं, तो वे केवल अपनी बीमारी का समाधान नहीं खोजतीं, बल्कि वे अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करती हैं। यहाँ का वातावरण, पूजा की प्रक्रिया और सामूहिक आस्था उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि वे अकेली नहीं हैं और उनके भीतर इस समस्या से लड़ने की क्षमता है।

थायराइड की समस्या भी इसी प्रकार की है, जो शरीर के संतुलन को प्रभावित करती है। जब व्यक्ति इस समस्या से जूझता है, तो उसे शारीरिक थकान के साथ-साथ मानसिक अस्थिरता का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह मंदिर एक ऐसा स्थान बन जाता है, जहाँ वह कुछ समय के लिए अपने तनाव से दूर होकर शांति का अनुभव कर सकता है। यह शांति उसके उपचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन जाती है।

यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि ऐसे मंदिर चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने अनेक बीमारियों के लिए प्रभावी उपचार विकसित किए हैं और उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी सत्य है कि मानसिक शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण उपचार की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाते हैं। इस दृष्टि से यह मंदिर एक पूरक भूमिका निभाता है, जहाँ व्यक्ति अपने मन को संतुलित कर सकता है।

दक्षिण भारत में ही स्थित Vaitheeswaran Koil भी इसी परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ भगवान शिव को 'वैद्य' के रूप में पूजा जाता है और सिद्धामृतम कुंड का जल औषधीय माना जाता है। भक्त इस जल को श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं और इसे रोगों से मुक्ति का माध्यम मानते हैं। यह परंपरा दर्शाती है कि भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता और स्वास्थ्य का संबंध कितना गहरा है।

इन सभी मान्यताओं का मूल आधार है—आस्था और आत्मबल। जब व्यक्ति किसी उच्च शक्ति पर विश्वास करता है, तो वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव करता है। यह ऊर्जा उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। मंदिरों में जाकर प्रार्थना करना, ध्यान करना और पूजा में भाग लेना एक प्रकार की मानसिक चिकित्सा के समान है, जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है।

आज के आधुनिक जीवन में, जहाँ हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के तनाव से गुजर रहा है, ऐसे स्थानों का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह मंदिर हमें यह सिखाते हैं कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आंतरिक संतुलन और मानसिक शांति भी उतनी ही आवश्यक है। जब मन शांत होता है, तो शरीर भी स्वस्थ रहने की दिशा में बेहतर कार्य करता है।

अंततः, Neelakandeswarar Temple केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है, जो व्यक्ति को उसके भीतर की शक्ति से परिचित कराता है। यहाँ आने वाले लोग केवल अपनी समस्याओं का समाधान नहीं खोजते, बल्कि वे अपने भीतर छिपी उस ऊर्जा को जागृत करने आते हैं, जो उन्हें जीवन की हर चुनौती से लड़ने का साहस देती है। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि सच्चा उपचार केवल दवाओं से नहीं, बल्कि विश्वास, संतुलन और आत्मबल से संभव होता है, और जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं, तभी जीवन में वास्तविक स्वास्थ्य और शांति का अनुभव किया जा सकता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

नाइट मैप में चमका उत्तर प्रदेश, ऊर्जा सुधारों से रोशनी बनी विकास का संकेत

Lucknow से लेकर पूरे Uttar Pradesh तक बीते कुछ वर्षों में जिस तरह ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव आया है, अब उसकी गूंज अंतरराष्ट्रीय मंच तक सुनाई देने लगी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA द्वारा जारी 'वर्ल्ड नाइट मैप' में उत्तर प्रदेश का प्रमुखता से उभरना केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि उस व्यापक परिवर्तन का प्रतीक है, जिसने राज्य की बुनियादी संरचना, आर्थिक गतिविधियों और जनजीवन को नई दिशा दी है।

रात के समय उपग्रह से ली गई तस्वीरों में जो चमक दिखाई देती है, वह केवल रोशनी नहीं होती, बल्कि उस क्षेत्र की सक्रियता, ऊर्जा पहुंच और विकास की गति का संकेत देती है। उत्तर प्रदेश का इस वैश्विक मानचित्र पर उभरना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य ने बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किया है। यह सुधार केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव गांव-गांव, शहर-शहर तक महसूस किया जा सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि नाइट-टाइम सैटेलाइट डेटा किसी भी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति, शहरीकरण और बुनियादी ढांचे का परोक्ष लेकिन प्रभावी संकेतक होता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का इस सूची में शामिल होना यह दर्शाता है कि राज्य में न केवल बिजली की उपलब्धता बढ़ी है, बल्कि उसकी निरंतरता और विश्वसनीयता में भी सुधार हुआ है। पहले जहां कई क्षेत्रों में बिजली कटौती आम बात थी, वहीं अब लगातार आपूर्ति ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है।

ऊर्जा विभाग के आंकड़े इस बदलाव की गहराई को और स्पष्ट करते हैं। प्रदेश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, जो पीक आवर्स में 28,000 मेगावाट के आसपास पहुंच जाती है। इतनी बड़ी मांग को पूरा करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन राज्य ने उत्पादन, खरीद और वितरण के स्तर पर समन्वित रणनीति अपनाकर इसे संभव बनाया है। यह समन्वय ही वह आधार है, जिस पर आज की स्थिर बिजली व्यवस्था खड़ी है।

ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ रही है। Ghatampur Thermal Power Project की तीसरी इकाई का सफल सिंक्रोनाइजेशन इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। इससे न केवल उत्पादन क्षमता में इजाफा हुआ है, बल्कि भविष्य में बढ़ती मांग को पूरा करने की क्षमता भी मजबूत हुई है। इसके साथ ही, राज्य ने ऊर्जा के विविध स्रोतों—तापीय, जलविद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा—पर संतुलित ध्यान देकर दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क में सुधार ने इस पूरी प्रक्रिया को और मजबूत बनाया है। प्रदेश में सैकड़ों नए उपकेंद्र स्थापित किए गए हैं और पुराने नेटवर्क को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया गया है। जर्जर लाइनों को बदलकर एक मजबूत और विश्वसनीय नेटवर्क तैयार किया गया है, जिससे बिजली की आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को काफी हद तक दूर किया जा सका है। इन सुधारों का सीधा असर लाइन लॉस में कमी के रूप में देखने को मिला है। एटी एंड सी लॉस में आई गिरावट यह दर्शाती है कि बिजली वितरण प्रणाली अधिक कुशल और पारदर्शी बनी है। जब लाइन लॉस कम होता है, तो उपभोक्ताओं को अधिक स्थिर और निर्बाध बिजली मिलती है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। डिजिटल तकनीकों का समावेश इस बदलाव को और प्रभावी बना रहा है। स्मार्ट मीटरिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए उपभोक्ताओं को अब अपनी बिजली खपत की रियल-टाइम जानकारी मिल रही है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि उपभोक्ताओं को अपनी खपत को नियंत्रित करने का अवसर भी मिला है। साथ ही, बिजली चोरी पर नियंत्रण के लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर सख्ती ने व्यवस्था को और मजबूत किया है। ऊर्जा क्षेत्र में हुए इन सुधारों का प्रभाव केवल तकनीकी या प्रशासनिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर राज्य के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी पड़ा है। किसानों को अब सिंचाई के लिए नियमित बिजली मिल रही है, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ी है। उद्योगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलने से उत्पादन में स्थिरता आई है और निवेश के नए अवसर पैदा हुए हैं। सेवा क्षेत्र में भी यह बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जहां डिजिटल सेवाओं और तकनीकी विकास के लिए लगातार बिजली जरूरी होती है।

'वर्ल्ड नाइट मैप' में उत्तर प्रदेश की बढ़ती चमक इस बात का भी संकेत है कि राज्य अब विकास के नए चरण में प्रवेश कर चुका है। यह केवल रोशनी का विस्तार नहीं, बल्कि उस सोच का परिणाम है, जिसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करके व्यापक विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। यह उपलब्धि भविष्य के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करती है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदम, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और तकनीकी नवाचार आने वाले समय में इस प्रगति को और गति देंगे।

आज जब दुनिया विकास के नए मानकों को तय कर रही है, ऐसे में उत्तर प्रदेश का 'वर्ल्ड नाइट मैप' में चमकना यह दर्शाता है कि सही नीतियों, प्रभावी क्रियान्वयन और तकनीकी नवाचार के जरिए किसी भी राज्य की तस्वीर बदली जा सकती है। यह उपलब्धि न केवल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह एक प्रेरणा भी है कि अगर संकल्प मजबूत हो, तो अंधेरे से उजाले की यात्रा संभव है।

पूर्व सैनिक ने 138 डिग्रियां हासिल कीं, यह संदेश दिया कि शिक्षा में उम्र कोई बाधा नहीं है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। शिक्षा और कला की कोई उम्र सीमा या बंधन नहीं होता। राजस्थान के एक पूर्व सैनिक ने इसे साबित कर दिया है। इतना ही नहीं, वे आलसी लोगों के लिए प्रेरणा भी बन गए हैं। राजस्थान के इस पूर्व सैनिक ने 138 डिग्रियां, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र हासिल किए हैं। यह आम लोगों की एक से पांच योग्यताओं की तुलना में कहीं अधिक है। झुंझुन जिले के निवासी दशरथ सिंह को हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के दीक्षांत समारोह में वैदिक अध्ययन में मास्टर डिग्री विशिष्टता के साथ पूरी करने पर उनकी नवीनतम योग्यता से सम्मानित किया गया।

55 वर्षीय दशरथ सिंह का दावा है कि उन्होंने 11 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इनमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज रिकॉर्ड शामिल हैं। ये सभी रिकॉर्ड शिक्षा के क्षेत्र में हैं। हालांकि पीटीआई को इन रिकॉर्ड्स की तस्वीरें मिली हैं, लेकिन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। दशरथ सिंह कहते हैं, "मेरे परिवार में कोई भी शिक्षित नहीं था, फिर भी मैंने एक छोटे से गांव के स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की। सरकारी स्कूल से 10वीं कक्षा पास करने के बाद, आर्थिक तंगी के कारण कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करना एक दूर का सपना लगता था।" उनका जन्म नवलगढ़ तालुका के खिरोद गांव में हुआ था, जो अपने युवाओं को सशस्त्र बलों में भेजने के लिए जाना जाता है।

उन्होंने 1988 में भारतीय सेना में प्रवेश किया। पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा अन्य स्थानों पर गैर-कमीशन अधिकारी के रूप में 16 वर्षों तक सेवा करने के बाद वे 2004 में सेना से सेवानिवृत्त हुए। किसान परिवार से आने वाले दशरथ सिंह कहते हैं कि सेवा के दौरान उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी शिक्षा "अधूरी" है। इसी भावना ने उन्हें सेवा के दौरान भी अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। इसलिए जब भी उन्हें दो महीने की वार्षिक छुट्टी मिलती, वे उस छुट्टी का उपयोग पढ़ाई के लिए करते और सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने अपने शौक को पूरे जोश के साथ आगे बढ़ाया।

"मैंने सबसे पहले वाणिज्य में स्नातक की डिग्री पूरी की, फिर नियमित छात्र के रूप में एलएलबी, एलएलएम, बीजेएमसी और बी.एड की पढ़ाई की। इसके साथ ही मैंने इग्नू, जैन विश्व भारती संस्था और निजी विश्वविद्यालयों से अन्य योग्यताएं भी हासिल कीं," दशरथ सिंह कहते हैं। अब तक उन्होंने तीन पीएचडी, सात स्नातक डिग्री, 46 स्नातकोत्तर डिग्री, 23 डिप्लोमा, सैन्य अध्ययन से संबंधित सात डिग्री और विभिन्न विषयों में 52 प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं।

लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद का सफर सिर्फ डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं था। सेवानिवृत्ति के बाद, मैंने सैनिकों के कल्याण में योगदान देने की आवश्यकता महसूस की। मैंने कानून की डिग्री प्राप्त की और वकालत शुरू कर दी। दशरथ सिंह बताते हैं, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद सेना की सतपा शक्ति कमान में कानूनी सलाहकार का पद संभाला और सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों से संबंधित मामलों को संभाला।

यह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति की कहानी है। अगर कोई अश्वेत व्यक्ति ठान ले तो क्या नहीं कर सकता?

मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके द्वारा वडोदरा स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट व्यवस्था की समीक्षा

समर सीज़न के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए वडोदरा मंडल प्रतिबद्ध

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके द्वारा आज वडोदरा स्टेशन का दौरा किया गया और समर सीज़न के दौरान यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं तथा क्राउड मैनेजमेंट व्यवस्था की समीक्षा की गई।

पश्चिम रेलवे के जनसम्पर्क अधिकारी श्रीअनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने इस दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए सभी अधिकारिओं एवं स्टेशन स्टाफ को यात्रिओं की सुविधा के लिए स्टेशन पर सभी व्यवस्थाओ को सुचारु रखने के निर्देश दिए। यात्रिओं की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए वडोदरा मंडल द्वारा क्राउड मैनेजमेंट के विशेष प्रयास किये गए है। इसके लिए वडोदरा स्टेशन पर 350 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल का एक होल्डिंग एरिया बनाया गया है,जहां यात्री ट्रेन आने से पहले आराम कर सकते हैं होल्डिंग एरिया में सीटिंग व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, पर्याप्त लाइटिंग जैसी मूलभूत सुविधाएं दी गई है। यात्रिओं की सहायता के लिए राउंड द क्लॉक टिकट चेकिंग और रेल सुरक्षा बल के अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की गयी है, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा न हो।

यात्री को टिकट लेने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए वडोदरा स्टेशन पर एक्स्ट्रा बुकिंग काउंटर खोले गए हैं। यात्रिओं के लिए टिकटिंग को आसान करते हुए टिकट चेकर द्वारा मोबाइल टिकटिंग की भी व्यवस्था की गयी है। स्टेशन पर यात्रियों की संख्या की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे द्वारा यात्रा की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवान प्रभावी समन्वय बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ड्यूटी के दौरान निर्बाध डिजिटल संचार के लिए वॉकी-टॉकी का उपयोग कर रहें हैं।

पश्चिम रेलवे का वड़ोदरा मंडल की आप सभी से अपील है टिकट खरीद कर यात्रा करें और स्टेशन पर उपलब्ध रेलवे कर्मचारियों के दिशा निर्देशों का पालन करें। पश्चिम रेलवे यात्रिओं के सफर को सुविधाजनक और आरामदायक बनाए के लिए प्रतिबध्द है।

उधना स्टेशन भगदड़ पर सियासत और सवाल: रेलवे के 'यू-टर्न' ने बढ़ाई शंकाएं, जिम्मेदारी तय करने की मांग तेज

सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर रविवार को हुई भगदड़ की घटना ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस छेड़ दी है। यात्रियों की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दे एक बार फिर केंद्र में आ गए हैं। घटना के अगले ही दिन हालात सामान्य भले दिखे हों, लेकिन इसके पीछे छिपे सवाल और विवाद अब भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ा विवाद उस समय खड़ा हुआ जब Western Railway के जनरल मैनेजर Ramashray Pandey ने घटनास्थल का दौरा कर लाठीचार्ज की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया।

जनरल मैनेजर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यात्रियों पर किसी भी प्रकार का लाठीचार्ज नहीं किया गया। उनके अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में जो दृश्य दिख रहे हैं, उनमें Railway Protection Force के जवान लाठियां जरूर चला रहे हैं, लेकिन वह यात्रियों पर नहीं, बल्कि स्टेशन की फेंसिंग पर मार रहे थे, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को "गलत नैरेटिव" बताते हुए कहा कि तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है।

हालांकि, रेलवे प्रशासन के इस बयान ने विवाद को शांत करने के बजाय और हवा दे दी है। प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों का कहना है कि स्थिति इतनी भयावह थी कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागना पड़ा। कई यात्रियों ने आरोप लगाया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया गया, जिससे अफरा-तफरी और बढ़ गई। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि यदि लाठीचार्ज नहीं हुआ, तो फिर भीड़ अचानक इतनी बेकाबू कैसे हो गई?

घटना के मूल में भीड़ प्रबंधन की विफलता को प्रमुख कारण माना जा रहा है। यात्रियों का आरोप है कि स्टेशन पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। न तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित बैरिकेडिंग थी और न ही यात्रियों को मार्गदर्शन देने के लिए पर्याप्त स्टाफ मौजूद था। पीने के पानी की कमी, टिकट काउंटरों पर अव्यवस्था और प्लेटफॉर्म पर अनियंत्रित भीड़ ने मिलकर हालात को विस्फोटक बना दिया। ऐसे में छोटी सी चूक भी बड़े हादसे का रूप ले सकती थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे देश में, जहां रेलवे रोजाना करोड़ों लोगों की आवाजाही का माध्यम है, वहां भीड़ प्रबंधन केवल एक औपचारिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक अत्यंत संवेदनशील जिम्मेदारी है। त्योहारों, छुट्टियों या विशेष ट्रेनों के दौरान यह जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उधना स्टेशन की घटना इस बात का संकेत है कि जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में कहीं न कहीं गंभीर कमी है। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू है—जवाबदेही का अभाव। जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो अक्सर जिम्मेदारी तय करने के बजाय बयानबाजी शुरू हो जाती है। प्रशासन अपनी छवि बचाने की कोशिश करता है, जबकि आम जनता जवाब चाहती है। उधना स्टेशन की घटना में भी यही देखने को मिल रहा है। एक तरफ रेलवे अधिकारी इसे सामान्य घटना बताने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यात्री इसे अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मान रहे हैं।

सोशल मीडिया ने इस पूरे घटनाक्रम को और भी संवेदनशील बना दिया है। वायरल वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लोगों के बीच तेजी से फैल रहे हैं, जिससे प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर साफ नजर आ रहा है। यही कारण है कि यह मामला अब केवल एक स्थानीय घटना नहीं रह गया, बल्कि पूरे देश में रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।

घटना के अगले दिन जब उधना स्टेशन पर सन्नाटा और सामान्य स्थिति देखने को मिली, तो यह एक तरह से राहत की बात जरूर थी, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। असली चुनौती यह है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए। इसके लिए केवल बयान देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ठोस और प्रभावी कदम उठाने होंगे।

विशेषज्ञ सुझाव दे रहे हैं कि रेलवे को अपने भीड़ प्रबंधन तंत्र को आधुनिक तकनीकों से लैस करना चाहिए। रियल-टाइम मॉनिटरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भीड़ विश्लेषण, बेहतर सिग्नलिंग और यात्रियों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जैसी व्यवस्थाएं लागू की जा सकती हैं। इसके अलावा, स्टाफ की संख्या बढ़ाना, नियमित प्रशिक्षण और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए विशेष ड्रिल भी जरूरी हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। रेलवे केवल एक परिवहन सेवा नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की जीवनरेखा है।

सोना वायदा में 763 रुपये और चांदी वायदा में 4741 रुपये की नरमी: क्रूड ऑयल वायदा 475 रुपये तेज

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 194758.01 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 22482.58 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 172275.43 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2617.28 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 14946.56 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सत्र के आरंभ में 153158 रुपये के भाव पर खूलकर, 153880 रुपये के दिन के उच्च और 152799 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 154609 रुपये के पिछले बंद के सामने 763 रुपये या 0.49 फीसदी लुढ़ककर 153846 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी अप्रैल वायदा 653 रुपये या 0.53 फीसदी घटकर 122680 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 71 रुपये या 0.46 फीसदी घटकर 15375 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। सोना-मिनी मई वायदा 151982 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 152450 रुपये और नीचे में 151256 रुपये पर पहुंचकर, 758 रुपये या 0.49 फीसदी घटकर 152418 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-टेन अप्रैल वायदा प्रति 10 ग्राम 152232 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 152665 रुपये और नीचे में 151576 रुपये पर पहुंचकर, 153398 रुपये के पिछले बंद के सामने 781 रुपये या 0.51 फीसदी घटकर 152617 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा 253453 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 254089 रुपये और नीचे में 250730 रुपये पर पहुंचकर, 257142 रुपये के पिछले बंद के सामने 4741 रुपये या 1.84 फीसदी घटकर 252401 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 4113 रुपये या 1.59 फीसदी औंधकर 254420 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 4150 रुपये या 1.61 फीसदी घटकर 254389 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

मेटल वर्ग में 2307.60 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा 3.6 रुपये या 0.28 फीसदी औंधकर 1269.3 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता अप्रैल वायदा 2.35 रुपये या 0.69 फीसदी की तेजी के संग 341.45 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम अप्रैल वायदा 1.95 रुपये या 0.54 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 365.4 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा अप्रैल वायदा 25 पैसे या 0.13 फीसदी घटकर 194.85 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

▶▶ कमोडिटी वायदाओं में 22482.58 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 172275.43 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 14946.56 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 4888.77 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा 8077 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 8388 रुपये और नीचे में 8077 रुपये पर पहुंचकर, 475 रुपये या 6.12 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 8242 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा 466 रुपये या 6 फीसदी बढ़कर 8234 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 252.3 रुपये के भाव पर खूलकर, 255.8 रुपये के दिन के उच्च और 250.5 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 250.2 रुपये के पिछले बंद के सामने 4.5 रुपये या 1.8 फीसदी की बढ़त के साथ 254.7 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा 4.6 रुपये या 1.84 फीसदी बढ़कर 254.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल अप्रैल वायदा 988.3 रुपये पर खूलकर, 90 पैसे या 0.09 फीसदी टूटकर 991 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 7728.55 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 7218.00 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1650.14 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 364.41 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 20.83 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 263.45 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 3670.94 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1188.14 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 1.50 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन कैंडी के वायदाओं में 0.14 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9739 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 60588 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 26992 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 373265 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 61804 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7734 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 24182 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 87178 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 14989 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 39621 लोट के स्तर पर था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मई 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 89.7 रुपये की बढ़त के साथ 235.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 255 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 95 पैसे के सुधार के साथ 5.25 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 222.5 रुपये की गिरावट के साथ 760 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 260000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2635.5 रुपये की गिरावट के साथ 2680.5 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.69 रुपये की गिरावट के साथ 1.42 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 335 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.26 रुपये की गिरावट के साथ 6.99 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मई 7000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 106.9 रुपये की गिरावट के साथ 185.2 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.65 रुपये की गिरावट के साथ 3.5 रुपये हुआ। सोना अप्रैल 145000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 29 रुपये की बढ़त के साथ 444 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 952.5 रुपये की बढ़त के साथ 4256.5 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1260 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.07 रुपये की गिरावट के साथ 11.6 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.14 रुपये की बढ़त के साथ 10.4 रुपये हुआ।

एसआईआर प्रक्रिया रोकने की मांग, बुद्धिजीवियों और वकीलों का विरोध, मतदाता अधिकारों के मुद्दे पर प्रस्ताव

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों में नगर निगमों से लेकर विधानसभाओं तक के चुनाव चल रहे हैं और चल रही मतदाता सूची समीक्षा (एसआईआर) का भी विरोध हो रहा है। ऐसे में बुद्धिजीवियों, वकीलों, छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह ने मतदाता सूची समीक्षा (एसआईआर) को तत्काल समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने इसे "नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध" बताया है और पुरानी मतदाता सूचियों को जारी रखने और उनके आधार पर चुनाव कराने का आह्वान किया है।

आयोजकों द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह मांग शनिवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मानवाधिकार संगठन "जन हस्तक्षेप" द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में रखी गई थी। संगोष्ठी में पूर्व चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर बद्री रैना, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की अध्यक्ष संगीता बरुआ पिशारोटी सहित अन्य उपस्थित थे। संगोष्ठी में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया।

पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल रोका जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, जिन लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, उनकी अपीलों पर तुरंत फैसला किया जाना चाहिए। उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। या फिर सभी के लिए मतदान के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए 2025 की अद्यतन मतदाता सूची का उपयोग किया जाना चाहिए।

प्रस्ताव में कहा गया है कि अन्यथा पश्चिम बंगाल विधानसभा के चल रहे चुनाव निरर्थक हो जाएंगे। एसआईआर प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग की भूमिका केवल मतदाता सूची में नाम शामिल करना है। वह नागरिकता दस्तावेजों की मांग या सत्यापन नहीं कर सकता। नागरिकता का निर्धारण गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इस संगोष्ठी के संयोजक जेएनयू के विकास बाजपेयी और सह-संयोजक पत्रकार अनिल दुबे थे।

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

संकेत एवं दूर संचार विभाग

ई–निविदा सूचना

निविदा संख्या : SnT_RTM_26_Tele_05, दिनांक : 17.04.2026

निम्न कार्य के लिए मंडल रेल प्रबंधक (संकेत एवं दूरसंचार) पश्चिम रेलवे रतलाम द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से ई–निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

कार्य का नाम : रतलाम मंडल में सिम्हास्थ 2028 के संबंध में विभिन्न स्टेशनों पर दूरसंचार यात्री सुविधाओं एवं विभिन्न सुविधाओं के उन्नयन तथा प्रतिस्थापन हेतु दूरसंचार सामग्री (OFC आधारित दूरसंचार अवसंरचना) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग का कार्य, **कार्य की अनुमानित लागत** : ₹ 4,79,46,820.12/- (रूपये चार करोड़ उन्यासी लाख छियालिस हजार आठ सौ बीस तथा बारह पैसे मात्र), **निविदा प्रपत्र का मूल्य** : शून्य, **जमानत राशि**: ₹ 9,58,900/-, **कार्य पूरा करने की अवधि** : नौ (09) माह, **ई–निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि व समय** : दिनांक 25/05/2026 समय 15.00 बजे तक, **ई–निविदा खोलने की तिथि व समय** : दिनांक 25.05.2026 समय 15:30 बजे तक, **वैधता** : निविदा खुलने की दिनांक से 60 दिन। निविदा **https://www.ireps.gov.in** वेबसाइट पर देखी जा सकती है। निविदाकार के पास Class-III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र आवश्यक है तथा IREPS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है केवल पंजीकृत निविदाकार ही ई–टेंडरिंग में भाग ले सकते है।

ADM/6/1/011

Follow us on: twitter.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

संकेत एवं दूर संचार विभाग

ई–निविदा सूचना

निविदा संख्या : SnT-RTM-26-Tele-06, दिनांक : 17.04.2026

निम्न कार्य के लिए मंडल रेल प्रबंधक (संकेत एवं दूरसंचार) पश्चिम रेलवे रतलाम द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से ई–निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

कार्य का नाम : रतलाम मंडल में सिम्हास्थ 2028 के संबंध में विभिन्न स्टेशनों पर दूरसंचार यात्री सुविधाओं एवं विभिन्न सुविधाओं के उन्नयन तथा प्रतिस्थापन हेतु दूरसंचार सामग्री (सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग का कार्य, **कार्य की अनुमानित लागत** : ₹ 8,09,57,465.47/- (रूपये आठ करोड़ नौ लाख सत्तावन हजार चार सौ पैंसठ और सैंतालीस पैसे मात्र), **निविदा प्रपत्र का मूल्य** : शून्य, **बयाना राशि**: ₹ 16,19,200/-, **कार्य पूरा करने की अवधि** : नौ (09) माह, **ई–निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि व समय** : दिनांक 28/05/2026 समय 15.00 बजे तक, **ई–निविदा खोलने की तिथि व समय** : दिनांक 28.05.2026 समय 15:30 बजे तक, **वैधता** : निविदा खुलने की दिनांक से 60 दिन। निविदा **https://www.ireps.gov.in** वेबसाइट पर देखी जा सकती है। निविदाकार के पास Class-III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होना चाहिए और IREPS Portal पर पंजीकृत होना आवश्यक है तथा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। केवल पंजीकृत निविदाकार ही ई–टेंडरिंग में भाग ले सकते है।

ADM/6/1/012

Follow us on: twitter.com/WesternRly

8 साल के मासूम की पुकार ने रोकी दो जिंदगियां, बूंदी में बाल विवाह पर करारा वार

राजस्थान के बूंदी जिले से आई यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि समाज के लिए आईना है—एक ऐसा आईना जिसमें एक आठ साल के बच्चे का साहस, संवेदनशीलता और जागरूकता साफ दिखाई देती है, जबकि दूसरी ओर सदियों पुरानी कुरीतियों की जड़ता भी उजागर होती है। जब बड़े लोग परंपराओं और सामाजिक दबावों के आगे चुप हो जाते हैं, तब एक मासूम की आवाज़ ने न सिर्फ एक बच्ची का भविष्य बचाया, बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि असल में जिम्मेदारी किसकी है।

यह घटना अक्षय तृतीया की रात की है—एक ऐसा दिन जिसे कई समुदायों में शुभ विवाह मुहूर्त माना जाता है। लेकिन इसी "शुभता" के नाम पर कई बार मासूम बचपन की बलि चढ़ा दी जाती है। बूंदी के एक गांव में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। आठ साल की एक बच्ची, जो अभी स्कूल जाती थी, खेलती थी, सपने देखती थी, उसकी शादी की तैयारियां चल रही थीं। उसी गांव में रहने वाला उसका एक दोस्त—सिर्फ आठ साल का एक बालक—यह सब देख रहा था। उसे यह समझ आ गया कि उसकी दोस्त के साथ कुछ गलत होने वाला है। उसने वह किया, जो शायद कई समझदार और बड़े लोग भी नहीं कर पाते—उसने आवाज़ उठाई।

उस मासूम ने Childline 1098 पर कॉल किया और बेहद सरल, लेकिन दिल को छू लेने वाले शब्दों में कहा—"भैया/दीदी, मेरी दोस्त की शादी रोक दीजिए। वह बहुत छोटी है, वह पढ़ना चाहती है।"

इस एक कॉल ने घटनाओं की दिशा बदल दी। सूचना मिलते ही चाइल्डलाइन की टीम सक्रिय हुई। जिला कोऑर्डिनेटर रामनारायण गुर्जर और केस वर्कर अर्चना मीना तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां जो दृश्य था, वह चौंकाने वाला था—पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली आठ साल की बच्ची की शादी की तैयारी पूरी हो चुकी थी।

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पुलिस और प्रशासन को सूचित किया गया। डबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास की मदद से मौके पर हस्तक्षेप किया गया और न सिर्फ उस बच्ची को, बल्कि वहां मौजूद एक और 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को भी बचाया गया, जिसकी शादी उसी शाम होने वाली थी। दोनों को सुरक्षित निकालकर Child Welfare Committee के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें आश्रय गृह भेजने का आदेश दिया गया।

यह घटना कई स्तरों पर सोचने को मजबूर करती है। एक तरफ एक छोटा बच्चा है, जिसे यह समझ है कि उसकी दोस्त का अधिकार क्या है—शिक्षा, बचपन और अपने भविष्य का चुनाव। दूसरी तरफ समाज के वे लोग हैं, जो आज भी बाल विवाह जैसी कुरीति को परंपरा के नाम पर ढो रहे हैं। यह विरोधाभास ही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है।

भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है, जो स्पष्ट रूप से 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी को अवैध ठहराता है। इसके बावजूद, खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में यह प्रथा आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी है। इसके पीछे कई कारण हैं—गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक दबाव, परंपराओं का गलत अर्थ, और कई बार कानून के प्रति लापरवाही।

बूंदी जिले में गुर्जर, मीना, मेघवाल, माली, रेगर, बरवा और भील जैसे समुदायों में अक्षय तृतीया के अवसर पर सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से बाल विवाह होने की घटनाएं अक्सर सामने आती रही हैं। यह दिन "अखा तीज" के नाम से जाना जाता है और इसे बिना मुहूर्त देखे विवाह करने के लिए शुभ माना जाता है। इसी मान्यता के चलते कई परिवार अपने बच्चों की कम उम्र में ही शादी कर देते हैं, बिना यह सोचे कि इसका उनके जीवन पर कितना गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

हालांकि प्रशासन अब इस समस्या को लेकर पहले से अधिक सतर्क है। बूंदी जिला प्रशासन ने एक बहुस्तरीय निगरानी तंत्र तैयार किया है, जिसमें 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन नंबर (0747-2442305), और जमीनी स्तर पर काम करने वाले आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविकाएं और स्वयंसेवकों को शामिल किया गया है। इन सभी को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

इस घटना के बाद प्रशासन ने और भी सख्ती दिखाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा चार निषेधाज्ञाएं जारी की गईं, जिनके तहत संभावित बाल विवाहों को रोकने के आदेश दिए गए। कई मामलों में समय रहते हस्तक्षेप कर नाबालिग लड़कियों को बचाया गया। एक मामले में 10वीं कक्षा की छात्रा की शादी 28 साल के युवक से कराई जा रही थी, जिसे न्यायिक आदेश से रोका गया। यह दिखाता है कि यदि प्रशासन, समाज और जागरूक नागरिक मिलकर काम करें, तो इस कुरीति को रोका जा सकता है।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक आठ साल के बच्चे को यह कदम क्यों उठाना पड़ा? समाज के बड़े लोग, परिवार, पड़ोसी—सब कहां थे? यह सवाल सिर्फ बूंदी या राजस्थान का नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए है। जब तक समाज खुद इस समस्या को स्वीकार नहीं करेगा और इसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, तब तक कानून और प्रशासन भी सीमित ही प्रभाव डाल पाएंगे।

इस घटना ने यह भी साबित किया कि जागरूकता की कोई उम्र नहीं होती। यदि बच्चों को सही शिक्षा और मूल्यों के साथ बड़ा किया जाए, तो वे भी समाज में बदलाव के वाहक बन सकते हैं। स्कूलों में बाल अधिकार, शिक्षा का महत्व और कानून की जानकारी देना बेहद जरूरी है, ताकि बच्चे खुद अपने और दूसरों के अधिकारों के प्रति सजग हो सकें।

इस मासूम बच्चे की हिम्मत ने न सिर्फ एक दोस्त का जीवन बचाया, बल्कि पूरे समाज को एक संदेश दिया है—गलत के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, चाहे आप कितने ही छोटे क्यों न हों। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बदलाव की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है—एक छोटे से फोन कॉल से, एक सच्ची भावना से, और एक मजबूत इरादे से।

आज जरूरत है कि हम इस घटना को सिर्फ एक खबर की तरह न देखें, बल्कि इससे सीख लें। हर नागरिक, हर परिवार और हर संस्था को यह समझना होगा कि बाल विवाह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक अपराध है—एक ऐसा अपराध जो बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल देता है। जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन अगर एक आठ साल का बच्चा बदलाव की शुरुआत कर सकता है, तो हम सब मिलकर इसे पूरी तरह खत्म क्यों नहीं कर सकते?

तेल की धार और भीड़ का लोभ: हादसे के बाद हाईवे पर 'लूट' का मंजर

राजस्थान के Tonk जिले में Tonk–Deoli National Highway 52 पर एक सड़क हादसा ऐसा दृश्य छोड़ गया, जिसने इंसानी प्रवृत्तियों पर कई सवाल खड़े कर दिए। यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, बल्कि कुछ ही मिनटों में वह एक तमाशे में बदल गई, जहाँ सड़क पर बहता सरसों का तेल लोगों के लिए जैसे 'मुफ्त की दौलत' बन गया और देखते ही देखते भीड़ उस पर टूट पड़ी।

घटना दाखिया गांव के पास हुई, जहाँ सरसों के तेल से भरा एक टैंकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने साइड से उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि टैंकर की साइड में बड़ा छेद हो गया और उसमें भरा हजारों लीटर सरसों का तेल तेज धार के साथ सड़क पर बहने लगा। कुछ ही पलों में हाईवे का दृश्य पूरी तरह बदल गया—जहाँ पहले गाड़ियाँ दौड़ रही थीं, वहीं अब पीले रंग की तेल की धार फैल चुकी थी।

शुरुआत में यह केवल एक हादसा था, लेकिन जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी भनक लगी, घटनास्थल पर भीड़ जमा होने लगी। देखते ही देखते यह भीड़ एक ऐसे दृश्य में बदल गई, जिसे देखकर हैरानी भी होती है और चिंता भी। लोग बाल्टी, डिब्बे, बोतल, कनस्तर—जो भी हाथ में आया, उसे लेकर दौड़ पड़े। कोई तेल को बहती धारा से भर रहा था, तो कोई सड़क के किनारे जमा हो रहे तेल को इकट्ठा कर रहा था।

कुछ लोग तो इतने 'जुगाड़' नजर आए कि उन्होंने छोटे-छोटे गड्ढों में जमा तेल को भी सावधानी से निकालकर अपने बर्तनों में भरना शुरू कर दिया। यह सिलसिला लगातार चलता रहा और किसी ने यह सोचने की जहमत नहीं उठाई कि यह एक दुर्घटना का परिणाम है, न कि कोई बांटी जा रही वस्तु।

इस दौरान हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। लेकिन भीड़ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए उस समय सबसे महत्वपूर्ण था जितना हो सके तेल अपने साथ ले जाना।

घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग खुलेआम तेल भरते और ले जाते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो केवल एक घटना का दस्तावेज नहीं, बल्कि उस मानसिकता को भी उजागर करता है, जहाँ मौके का फायदा उठाना एक सामान्य व्यवहार बन जाता है।

सूचना मिलते ही Mehandwas Police Station की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस ने लोगों को टैंकर के पास से हटाया और धीरे-धीरे भीड़ को वहां से हटाया। इसके बाद यातायात को बहाल करने की कोशिश की गई। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। टैंकर का अधिकांश तेल सड़क पर बह चुका था और बड़ी मात्रा में लोग उसे अपने साथ ले जा चुके थे।

टैंकर चालक ने बताया कि वह कोटा से सरसों का तेल लेकर जा रहा था, तभी दाखिया गांव के पास पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में टैंकर को भारी नुकसान हुआ और करीब 8 से 10 टन तेल सड़क पर फैल गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई। लेकिन इस घटना ने एक अलग तरह की चर्चा को जन्म दे दिया है।

यह सवाल उठता है कि क्या किसी दुर्घटना के बाद इस तरह की लूट उचित है? क्या यह केवल 'मौके का फायदा' है या फिर यह समाज में बढ़ती संवेदनहीनता का संकेत है? जब किसी हादसे के बाद लोगों का पहला प्रतिक्रिया मदद करने के बजाय सामान उठाने की हो, तो यह सोचने की जरूरत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं।

यह घटना केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सामाजिक आईना है। इसमें एक ओर लापरवाही से हुआ हादसा है, तो दूसरी ओर उस हादसे के बाद उभरती भीड़ की मानसिकता। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम संवेदनशील समाज की ओर बढ़ रहे हैं या फिर धीरे-धीरे संवेदनहीन होते जा रहे हैं।

सरहदों से लंबा इंतज़ार, आखिर जोधपुर में सजी प्रेम की दहलीज़

राजस्थान के Jodhpur शहर के पाल क्षेत्र में सोमवार का दिन किसी साधारण दिन जैसा नहीं था। एक घर के आंगन में वर्षों से संजोया गया सपना आखिरकार सच हो रहा था। यह सिर्फ एक बहू का गृह प्रवेश नहीं था, बल्कि 15 साल लंबे इंतजार, जुदाई और उम्मीदों की जीत का क्षण था। जब दरवाज़े पर आरती की थाली सजी, फूलों की खुशबू फैली और परिवार के चेहरे खुशी से चमक उठे, तो हर आंख में नमी भी थी और मुस्कान भी।

यह कहानी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमित सुथार और पाकिस्तान की डॉक्टर रक्षा सुथार की, जिनका रिश्ता किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। इस रिश्ते की शुरुआत उस समय हुई थी, जब अमित का परिवार पाकिस्तान में ही रहता था। परिवार के बड़ों ने पारंपरिक तरीके से रक्षा के साथ उनका रिश्ता तय कर दिया था। सब कुछ सामान्य था, भविष्य के सपने बुने जा रहे थे, लेकिन तभी समय ने करवट ली और परिस्थितियां बदल गईं।

साल 2011 में बेहतर भविष्य की तलाश में अमित सुथार अपने पिता प्रदीप सुथार के साथ पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए और Jodhpur में बस गए। यह फैसला उनके जीवन के लिए नया अध्याय लेकर आया, लेकिन इसी के साथ उनके रिश्ते पर एक लंबी दूरी की छाया भी पड़ गई। रक्षा, जो उनकी मंगेतर थीं, सरहद के उस पार ही रह गईं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों ने इस दूरी को और कठिन बना दिया। वीजा प्रक्रिया इतनी जटिल और अनिश्चित थी कि हर कोशिश उम्मीद जगाती और फिर निराशा में बदल जाती। साल दर साल गुजरते गए।

अमित ने भारत में अपने करियर को आगे बढ़ाया और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, वहीं रक्षा ने पाकिस्तान में अपनी पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बनने का सपना साकार किया। दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनके बीच का रिश्ता समय और दूरी के बावजूद अडिग रहा। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास की कहानी थी, जिसमें हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता और एक अधूरी चाहत के साथ खत्म होता। जब बार-बार की कोशिशों के बावजूद वीजा नहीं मिल पाया, तो दोनों परिवारों ने एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसा देश चुना, जो दोनों के लिए 'न्यूट्रल' था—Nepal।

साल 2025 में यह योजना साकार हुई। 2 जून को अमित अपने परिवार के साथ काठमांडू पहुंचे और रक्षा भी अपने परिवार के साथ वहां पहुंचीं। काठमांडू की धरती पर दोनों ने सात फेरे लिए और शादी के बंधन में बंध गए। यह पल उनके लिए बेहद खास था, लेकिन इसके साथ ही एक और जुदाई की शुरुआत भी थी। शादी के बाद नियमों के चलते अमित को अकेले भारत लौटना पड़ा और रक्षा को वापस पाकिस्तान जाना पड़ा। यह जुदाई पहले से भी ज्यादा कठिन थी, क्योंकि अब वे केवल मंगेतर नहीं, बल्कि पति-पत्नी थे। इसके बाद शुरू हुआ एक और लंबा इंतजार—कागजी प्रक्रियाओं का, दूतावासों के चक्कर का और एक ऐसे वीजा का, जो उन्हें एक साथ रहने की अनुमति दे सके। करीब 10 महीनों तक यह संघर्ष चलता रहा। हर दस्तावेज, हर आवेदन और हर प्रक्रिया में समय लगता गया, लेकिन उम्मीद बनी रही।

आखिरकार, जब केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah और केंद्रीय मंत्री Gajendra Singh Shekhawat के हस्तक्षेप के बाद राहत मिली, तो जैसे वर्षों का बोझ हल्का हो गया। रक्षा को 45 दिनों का विजिटर वीजा मिला और वह भारत आने में सफल रहीं।

जब रक्षा सुथार अपने ससुराल, Jodhpur के पाल क्षेत्र में पहुंचीं, तो वहां का दृश्य भावनाओं से भरा हुआ था। सास-ससुर ने अपनी बहू का स्वागत वैसे किया, जैसे कोई लंबे समय बाद अपने खोए हुए सदस्य को वापस पाता है। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन उन खुशियों में वर्षों के इंतजार की थकान और संघर्ष की यादें भी शामिल थीं।

युवा संकल्प से सशक्त होगा लोकतंत्र: राजकोट के रामकृष्ण आश्रम में मतदान जागरूकता की नई अलख

गुजरात के राजकोट में लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक प्रेरक पहल देखने को मिली, जहां युवाओं ने न केवल मतदान के महत्व को समझा, बल्कि उसे जीवन का अनिवार्य कर्तव्य मानते हुए सक्रिय भागीदारी का संकल्प भी लिया। यह आयोजन ऐसे समय में हुआ है, जब देशभर में चुनावी माहौल धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है और मतदाता जागरूकता को लेकर प्रशासनिक स्तर पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राजकोट में यह पहल इस बात का संकेत है कि लोकतंत्र की जड़ें तभी मजबूत होंगी, जब युवा वर्ग न सिर्फ जागरूक होगा, बल्कि सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाएगा।

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन Ramakrishna Mission Ashram में किया गया, जहां 'विवेकानंद सर्विस कोर' के अंतर्गत युवाओं के लिए एक विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मतदान के लिए प्रेरित करना नहीं था, बल्कि युवाओं के भीतर नेतृत्व क्षमता, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना भी था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और पूरे उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस पर्व से जुड़ने की प्रतिबद्धता दिखाई।

इस अभियान को Election Commission of India की पहल SWEEP के तहत संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को शिक्षित करना और उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। ज़िला चुनाव अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश के मार्गदर्शन में राजकोट जिले में यह अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। प्रशासन का स्पष्ट लक्ष्य है कि कोई भी मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे और हर नागरिक मतदान के महत्व को समझे।

कार्यक्रम के दौरान युवाओं को लोकतंत्र की मूल अवधारणाओं से अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि मतदान केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, जो देश के भविष्य को तय करती है। प्रशिक्षकों ने युवाओं को यह समझाया कि एक-एक वोट की कीमत क्या होती है और किस तरह यह राष्ट्र की नीतियों, विकास और शासन व्यवस्था को प्रभावित करता है।

इसके साथ ही, युवाओं को नेतृत्व के गुण, टीमवर्क, सामाजिक सेवा और नैतिक मूल्यों पर भी प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे समाज में सकारात्मक बदलाव के वाहक बन सकें।

कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह था, जब सभी प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से 'मतदान की शपथ' ली। इस शपथ के माध्यम से उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे न केवल आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, बल्कि अपने परिवार, मित्रों और समाज के अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। यह शपथ केवल एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी का प्रतीक थी, जिसे युवाओं ने पूरे विश्वास और उत्साह के साथ स्वीकार किया।

इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसमें युवाओं को केवल मतदाता के रूप में नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक के रूप में तैयार किया जा रहा है। उन्हें यह बताया गया कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें नागरिकों की भागीदारी हर स्तर पर जरूरी होती है। चाहे वह सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाना हो, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना हो या फिर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना—हर क्षेत्र में युवाओं की भूमिका अहम है।

तुगलकी फरमान के साये में थमी शहनाइयाँ बहिष्कार के डर में जकड़ा एक परिवार

राजस्थान के Jalore जिले के Bhinmal से सामने आई यह घटना केवल एक स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि उस सामाजिक विडंबना का प्रतीक है, जहाँ आज भी कुछ स्वयंभू लोग कानून से ऊपर खड़े होकर परिवारों की खुशियों पर पहरा लगाने की कोशिश करते हैं। भादरड़ा रोड निवासी वरदाराम माली का घर इस समय उसी त्रासदी से गुजर रहा है, जहाँ शहनाइयों की जगह सन्नाटा और उत्सव की जगह भय ने ले ली है।

घर में इन दिनों खुशियों का माहौल होना चाहिए था। बेटे और दो बेटियों की शादी की तैयारियाँ चल रही थीं। रिश्तेदारों को न्योते भेजे जा रहे थे, आंगन में मंडप की कल्पना की जा रही थी, और परिवार के हर सदस्य की आँखों में एक नए जीवन की शुरुआत का सपना था। लेकिन अचानक एक ऐसा फरमान आया, जिसने इन सभी सपनों को जैसे रोक दिया।

बताया जा रहा है कि इस पूरे विवाद की जड़ परिवार के भतीजे विक्रम कुमार का लिव-इन रिलेशनशिप है। एक निजी जीवन से जुड़े इस फैसले को समाज के कुछ लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। इसके बाद एक अवैध पंचायत बुलाई गई, जिसमें कुछ स्वयंभू पंचों ने मिलकर ऐसा निर्णय सुनाया, जिसने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया।

इस पंचायत में शामिल समरथाराम, दीपाराम, बाबुलाल, जगदीश, सोमताराम, सरदाराराम और मांगीलाल ने मिलकर विक्रम कुमार पर 31 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि उसके बहनोई पांचाराम पर 4 लाख रुपये का दंड ठोक दिया गया। इसके साथ ही दोनों को समाज से बहिष्कृत कर उनका 'हुक्का पानी' बंद करने का फरमान जारी किया गया। ग्रामीण परिवेश में यह दंड केवल एक सामाजिक सजा नहीं, बल्कि व्यक्ति के अस्तित्व को ही खत्म कर देने जैसा होता है।

लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब पंचायत ने यह घोषणा की कि जो भी व्यक्ति इस परिवार की शादी में शामिल होगा, उसे भी समाज से बाहर कर दिया जाएगा और उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इस एक फैसले ने पूरे माहौल को बदल दिया। रिश्तेदार, जो पहले खुशी-खुशी आने वाले थे, अब डर के कारण पीछे हटने लगे हैं।

घर के भीतर अब उत्सव की जगह चिंता ने ले ली है। दूल्हा और दुल्हन, जो अपने नए जीवन के सपने देख रहे थे, अब इस सोच में डूबे हैं कि उनकी शादी में कौन आएगा। परिवार के बड़े-बुजुर्ग, जो पहले तैयारियों में जुटे थे, अब हर पल किसी अनहोनी की आशंका में जी रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि यह पूरा मामला केवल सामाजिक नियमों का नहीं, बल्कि दबाव बनाने की एक सोची-समझी रणनीति है। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर पहले ही Bhinmal Police Station में मुकदमा दर्ज है और गवाही देने से नाराज ये लोग अब उन्हें मुकदमा वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लगातार मिल रही धमकियों और सामाजिक बहिष्कार ने परिवार को मानसिक रूप से तोड़ दिया है।

स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि दूल्हा-दुल्हन सहित परिवार के कई सदस्य रात के समय थाने पहुंचे और अपनी आपबीती सुनाई। उनकी आवाज में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई, ताकि वे बिना किसी भय के अपनी शादियाँ कर सकें।

वरदाराम माली ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। उनका कहना है कि वे कानून पर भरोसा रखते हैं, लेकिन जिस तरह से समाज के कुछ लोग अपने नियम थोप रहे हैं, वह चिंता का विषय है।

पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की गहराई से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या आज भी समाज के कुछ हिस्सों में कानून से ऊपर स्वयंभू पंचायतें काम कर रही हैं? क्या किसी व्यक्ति के निजी जीवन के फैसले को आधार बनाकर पूरे परिवार को सजा देना न्यायसंगत है? और सबसे बड़ा सवाल—क्या हम सच में एक ऐसे समाज में जी रहे हैं, जहाँ हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता है?

भारत का संविधान हर नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों को लेकर भी न्यायपालिका कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि यह व्यक्तिगत पसंद का हिस्सा है। ऐसे में किसी पंचायत द्वारा इस तरह का फरमान जारी करना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि यह मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है।

आज वरदाराम माली का परिवार जिस पीड़ा से गुजर रहा है, वह केवल एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि उस संघर्ष का प्रतीक है, जो आधुनिक कानून और पुरानी सोच के बीच चल रहा है। जब तक समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता नहीं बढ़ेगी, तब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे और लोगों की खुशियाँ इसी तरह डर के साये में घुटती रहेंगी।

'लेट्स वोट' से जागा सूरत: लोकतंत्र के पर्व को जन-जन तक पहुंचाने की नई पहल

गुजरात के सूरत शहर में लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से एक अनूठी और प्रेरणादायक पहल सामने आई है, जिसने मतदान जागरूकता के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ते हुए डिजिटल और रचनात्मक माध्यमों का सहारा लिया है। आगामी लोकल बॉडी चुनावों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई 'लेट्स वोट' डॉक्यूमेंट्री न सिर्फ एक फिल्म है, बल्कि एक संदेश है—एक ऐसा संदेश जो हर नागरिक को उसके अधिकार और कर्तव्य की याद दिलाता है। यह पहल इस बात का उदाहरण है कि जब सामाजिक संस्थाएं, प्रशासन और नागरिक समाज एक साथ आते हैं, तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं।

इस डॉक्यूमेंट्री को Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry और Surat Citizen Council ने मिलकर तैयार किया है। इसका उद्देश्य पूरी तरह गैर-राजनीतिक है, ताकि किसी भी प्रकार के पक्षपात से दूर रहते हुए नागरिकों को निष्पक्ष रूप से मतदान के लिए प्रेरित किया जा सके। इस फिल्म की लॉन्चिंग 20 अप्रैल 2026 को सूरत के सरसाना स्थित उषाकांत मारफतिया सेमिनार हॉल में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में की गई, जहां शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

तीन मिनट की इस लघु डॉक्यूमेंट्री को बेहद प्रभावशाली तरीके से तैयार किया गया है, जिसमें संदेश को सरल, स्पष्ट और भावनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म की स्क्रिप्ट Dr. Mukul Chokshi ने लिखी है, जबकि निर्देशन Vaibhav Desai ने किया है। संगीत Jimmy Desai द्वारा तैयार किया गया है और प्रोडक्शन की जिम्मेदारी Setu Upadhyay ने निभाई है। इस पूरी टीम ने मिलकर एक ऐसा कंटेंट तैयार किया है, जो कम समय में अधिक प्रभाव छोड़ने की क्षमता रखता है। इस पहल को खास बनाता है इसमें शामिल शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों का योगदान। Anupam Singh Gehlot, Dr. Saurabh Pardhi, M. Nagarajan, Veer Narmad South Gujarat University के वाइस चांसलर Dr. Kishor Singh Chavda और अभिनेत्री Yukti Randeria जैसे नामों की मौजूदगी इस डॉक्यूमेंट्री को और भी विश्वसनीय और प्रभावशाली बनाती है। इन सभी ने अपने-अपने तरीके से नागरिकों को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है।

इससे पहले भी 'लाइन लगावो' नामक एक जागरूकता फिल्म बनाई गई थी, लेकिन उस समय सोशल मीडिया का प्रभाव सीमित था, जिसके कारण वह पहल व्यापक स्तर पर लोगों तक नहीं पहुंच सकी। इस बार आयोजकों ने समय की जरूरत को समझते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का पूरा उपयोग करने का निर्णय लिया है। 'लेट्स वोट' को न सिर्फ सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जाएगा, बल्कि शहर के सिनेमाघरों में भी प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि हर वर्ग तक इसका संदेश पहुंचे।

आज के डिजिटल युग में जहां सूचना का प्रवाह तेज है, वहीं लोगों का ध्यान आकर्षित करना भी एक चुनौती बन गया है। ऐसे में छोटी, प्रभावी और भावनात्मक सामग्री ही अधिक असर डालती है। 'लेट्स वोट' इसी रणनीति का हिस्सा है, जो कम समय में दर्शकों के मन पर गहरी छाप छोड़ने का प्रयास करती है। यह फिल्म केवल मतदान के लिए प्रेरित नहीं करती, बल्कि यह भी सिखाती है कि सही उम्मीदवार का चयन कैसे किया जाए और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में क्या भूमिका निभाई जाए।

इस पहल का व्यापक महत्व इसलिए भी है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अक्सर यह देखा जाता है कि मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहता है। व्यस्त जीवनशैली, उदासीनता या यह सोच कि "एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा"—ये सभी कारण लोगों को मतदान से दूर रखते हैं। 'लेट्स वोट' जैसी पहल इन मानसिकताओं को बदलने का प्रयास करती है और यह संदेश देती है कि हर एक वोट की कीमत होती है।

लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसे हर नागरिक को निभाना होता है। जब लोग अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं, तभी एक सशक्त और प्रतिनिधिक सरकार का गठन संभव होता है। इस दृष्टिकोण से सूरत की यह पहल न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। अंततः, 'लेट्स वोट' केवल एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत है—एक ऐसा आंदोलन जो जागरूकता, जिम्मेदारी और सहभागिता के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि इस तरह की पहल देश के अन्य शहरों में भी अपनाई जाए, तो निश्चित ही आने वाले समय में मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी और लोकतंत्र की जड़ें और भी मजबूत होंगी।